

मुख्य समाचार

- नीति आयोग की बैठक में विकसित भारत के दृष्टि पत्र पर हुई चर्चा, प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए अनुकूल नीति बनाने पर दिया बल।
- केन्द्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने केन्द्रीय बजट को बताया सर्वस्पर्शी, कहा— हिमाचल में विकास की गति को मिलेगा बल।
- मुख्यमंत्री ने कहा— राज्य सरकार आरक्षित वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध, अनेक योजनाओं के माध्यम से किया जा रहा है उत्थान।
- सांसद सिकंदर कुमार ने राज्यसभा में उठाया यूरैनियम से जुड़ा मामला, केन्द्रीय मंत्री जीतेन्द्र सिंह ने कहा—केन्द्र सरकार हिमाचल में यूरैनियम अयस्क भंडारों की कर रही है खोज।

.....

नीति आयोग

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत 2047 प्रत्येक भारतीय की महत्वाकांक्षा है। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में आज नीति आयोग की नौवीं शासी परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों से सीधे जुड़े होने के कारण राज्य इस उद्देश्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रौद्योगिकी और भू-राजनीति व अवसरों के लिए परिवर्तन का दशक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को इन अवसरों का लाभ उठाकर अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए अनुकूल नीति बनाने की आवश्यकता है। नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रगति का माध्यम है और देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।

हर्ष मल्होत्रा

केन्द्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा है कि हिमाचल को केन्द्रीय बजट में बहुत कुछ मिला है और इस प्रदेश का नाम बजट में अंकित किया गया है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि हिमाचल में अनेक

सड़क परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है और केंद्रीय बजट से इन्हें बल मिलेगा। मल्होत्रा ने कहा कि हिमाचल को केंद्रीय आमदनी में से 10 हजार 3 सौ 51 करोड़ 82 लाख रुपये की राशि प्राप्त होगी और सड़कों, सुरंगों, कृषि, बागवानी और युवा शक्ति पर बजट में विशेष बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि रेल बजट में भी हिमाचल को बड़ा बजट मिला है और प्रदेश की रेल परियोजनाओं को 2 हजार 6 सौ 98 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसके माध्यम से भानुपल्ली-बिलासपुर, नंगल- तलवाड़ा और चंडीगढ़-बद्दी रेल लाईन के कार्य को गति मिलेगी। मल्होत्रा ने कहा कि शिमला-पालमपुर, बैजनाथ, पपरोला और अम्ब-इंदौरा में विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूर्व यूपीए सरकार के मुकाबले एनडीए सरकार ने हिमाचल को 2 सौ 64 फीसदी अधिक आर्थिक मदद दी है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय बजट सर्वस्पर्शी है और इसमें समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है।

राज्यपाल

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने अध्यापकों से राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2023 को सफलतापूर्वक लागू करने का आह्वान किया है। हमीरपुर ज़िले के बणी में आज उन्होंने विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के प्रधानाचार्यों की चार दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया, इसमें 5 सौ से अधिक प्रधानाचार्य भाग ले रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2023 देश में शिक्षा की यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा और इसे लागू करना शिक्षकों की नेतृत्व क्षमता, दृष्टिकोण व समर्पण पर निर्भर करता है। शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि विद्या भारती ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर एक अच्छी पहल की है और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के परिवर्तनकारी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अध्यापक एक निर्णायक भूमिका में हैं।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए वचनबद्ध है और इनके लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत 50 हजार रुपये से कम वार्षिक आय वाले आरक्षित वर्गों के परिवारों को मकान निर्माण के लिए डेढ़ लाख रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में एक हजार एक सौ 50 लाभार्थियों को आवास सुविधा के लिए 17 करोड़ 25 लाख रुपये जारी किए गए हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लोगों को औजारों व उपकरणों की खरीद के लिए एक हजार 3 सौ रुपये जबकि सिलाई

मशीन के लिए सरकार की ओर से एक हजार 8 सौ रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण के लिए राज्य सरकार ने लगभग 25 करोड़ रुपये की 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

अनुराग ठाकुर

पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेश के निजी अस्पतालों में हिमकेयर कार्ड बंद करने के राज्य सरकार के निर्णय पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं है और पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई योजनाओं को भी अब बंद किया जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि निजी अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए हिमकेयर योजना लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, ऐसे में राज्य सरकार का इसे बंद करने का फैसला पूरी तरह गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश में चिकित्सा सेवाएं चरमरा गई हैं और डायलिसिस जैसी सुविधा के लिए मरीजों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने प्रदेश व प्रदेश के बाहर एक सौ 41 निजी स्वास्थ्य संस्थानों में हिमकेयर योजना की सुविधा दी थी, मगर अब कांग्रेस सरकार इसे बंद करने जा रही है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से कार्य करने का आरोप भी लगाया।

जयराम

विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री की प्रदेश के हित में कोई रुचि नहीं है और नीति आयोग की बैठक में न जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नीति आयोग की बैठक में शामिल न होने से प्रदेश का नुकसान होगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास हिमाचल के हितों को केन्द्र के समक्ष रखने का मौका था लेकिन उन्होंने इसे गवां दिया। विपक्ष के नेता ने कहा कि हिमाचल जैसे छोटे राज्य को केन्द्र सरकार का सहयोग मिलना ज़रूरी है और मुख्यमंत्री को नीति आयोग की बैठक में हर हाल में भाग लेना चाहिए था। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए राज्य सरकार की ओर से बनाई गई कैबिनेट सब-कमेटी मात्र रस्म अदायगी है।

अग्निहोत्री

धर्मशाला बस अड्डे का नाम पूर्व मंत्री जी.एस. बाली के नाम पर रखा जाएगा। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज कांगड़ा ज़िले के नगरोंटा में स्वर्गीय जी.एस. बाली

की स्मृति में आयोजित चार दिवसीय मेले के समापन अवसर पर ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में जी.एस. बाली का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने अनेक विभागों का आधुनिकीकरण किया। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि युवाओं के लिए राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना लागू की है और ई-टैक्सी खरीदने पर 50 फीसदी अनुदान दिया जाएगा। इन ई-टैक्सियों को कम से कम चार वर्ष के लिए सरकारी विभागों द्वारा अनुबंध पर लिया जाएगा।

सिकंदर कुमार

केन्द्र सरकार हिमाचल में यूरेनियम अयस्क भंडारों की खोज कर रही है और इसके लिए हमीरपुर, ऊना व शिमला जिले में तीन यूरेनियम निक्षेप स्थापित किए गए हैं। केन्द्रीय राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने राज्यसभा में सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार द्वारा इस संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। सिकंदर कुमार ने अपने प्रश्न में केन्द्र सरकार से प्रदेश में यूरेनियम उपचार संयंत्र स्थापित करने के बारे में जानकारी मांगी थी। जितेन्द्र सिंह ने बताया कि ऊना जिले के राजपुरा में 3 सौ 64 टन, शिमला जिले के कशा कलाड़ी में 2 सौ टन और मंडी जिले के तलेली में 2 सौ 20 टन यूरेनियम ऑक्साइड मिलने का अनुमान है। इसके अलावा हमीरपुर जिले के मसनवल में भी यूरेनियम अयस्क के भंडार मिलने की संभावना है। सिकंदर कुमार ने खाद्य फसलों के उत्पादन का मामला भी उठाया, जिसके जवाब में केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पिछले 5 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत हिमाचल को लगभग साढ़े 38 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है।

शांडिल

स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती चरणबद्ध ढंग से की जा रही है। उन्होंने आज सोलन जिले के सायरी में नागरिक अस्पताल की रोगी कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। धनीराम शांडिल ने कहा कि सायरी अस्पताल को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया है और अस्पताल में जल्द ही सभी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी।